

India aims to triple natural gas share to 15% by 2030: Teli

New Delhi: India is embarking on an ambitious trajectory to amplify its existing 6% share of natural gas in the energy mix to a formidable 15% by 2030, as the government presses forward with a suite of comprehensive measures, said minister of state for petroleum and natural gas Rameswar Teli.



SAURAV ANAND

GLOBAL BIOFUELS ALLIANCE

India reaching out to non-G20 nations as major energy producers remain evasive

SUBHAYAN CHAKRABORTY
New Delhi, 10 August

India is actively reaching out to nations outside the G20 grouping, seeking their participation in the proposed Global Biofuels Alliance (GBA), multiple officials told *Business Standard*, even as major energy producers like Russia, China and Saudi Arabia remain unconvinced about joining the multilateral initiative.

India's diplomatic missions are reaching out to a host of nations to ensure a full house when the Alliance is inaugurated by Prime Minister Narendra Modi during the G-20 Leaders Summit on September 9-10, they said.

On July 22, India held a global meet on the issue, on the sidelines of the G-20 energy ministers meeting in Goa.

After deliberations, it announced that 19 countries have expressed their interest in being the initiating members of the Alliance, without naming them.

However, at least 7 of the nations whose energy ministers attended the summit and unanimously supported

the formation of the Alliance, were not G-20 members. These countries include Bangladesh, Kenya, Mauritius, Paraguay, Seychelles, the UAE and Uganda. "More countries are now being invited to join the GBA and many have responded positively. We have also heard specific inputs from the least developed nations. All these will be taken into account when the Alliance is launched and its policy goals are framed," an official said.

Apart from nations in the immediate neighbourhood, and its long list of allies in Africa, India is expecting support from Latin American nations, marshalled by the United States (US), which has given its support to the GBA.

New Delhi is also counting on the support of the Central Asian nations part of the Shanghai Cooperation Agreement bloc, which recently decided to collaborate on emerging fuel technology, energy modelling, and transition goals. But within the G20 grouping, Russia and Saudi Arabia have not come fully on board owing to their fear that the alliance will intensify the grow-

SEEKING SUPPORT

- Russia and Saudi Arabia rely on crude oil to finance their Budget
- PM to inaugurate the Alliance during the G20 Leaders Summit in September
- Along with neighbouring countries and allies in Africa, India expecting support from Latin American nations

ing clamour against fossil fuels. Both Moscow and Riyadh rely on crude oil to finance large chunks of their budgets, and have called for continuing investment into traditional hydrocarbons during the global energy transition.

Meanwhile, China has shown "little interest in the proposal", the official added. India can't do much to convince China to join the Alliance since it has competed with India on major multi-lateral initiatives. Beijing has also prioritised biofuels in its national carbon

reduction and fuel sufficiency plans and produces almost as much ethanol as India, according to the International Energy Agency (IEA).

However, officials from the Petroleum and Natural Gas Ministry said partners such as Russia and Saudi Arabia have been taken into confidence and been told the GBA will work in collaboration with relevant existing regional and international agencies as well as initiatives in the bioenergy, bio-economy, and energy transition fields more broadly. This includes the Clean Energy Ministerial Biofuture Platform, the Mission Innovation Bioenergy initiatives, and the Global Bioenergy Partnership (GBEP). Other officials, however, downplayed the realistic impact of the nations' not joining the alliance.

"The US holds a 55 per cent share followed by Brazil at 27 per cent and India at 3 per cent. India's share is expected to quickly rise. In terms of the global impact that such an alliance will bring, all the key participants are already ready," a NITI Aayog official said.



Oil India registers hike in Profit after Tax in Q1 FY'24

Oil India Limited (OIL) posted a rise of 3.7% in its Profit After Tax (PAT) in the first quarter of financial year 2024 at Rs 1,613.43 crore against Rs 1,555.49 crore in Q1 of last financial year. The growth comes on the strength of a 5.3% growth in its crude oil production to 0.820 MMT in Q1 of FY 24 vis-à-vis 0.729 MMT produced in Q1 of last FY, coupled with lower operating costs. EPS for the period has increased to Rs 14.88/share as compared to Rs 14.34/share in the previous comparative period.

SJVN signs MoUs with ONGC and SSL



Nand Lal Sharma, Chairman & Managing Director, SJVN informed that SJVN has signed separate Memorandums of Understanding (MoU) with Oil & Natural Gas Corporation (ONGC) and Sambhar Salts Limited (SSL), a subsidiary of Hindustan Salts Limited. Nand Lal Sharma apprised that the MoU inked with ONGC will pave a way for joint development of renewable energy projects. This will include Offshore & Onshore Solar, Wind, Hybrid, RTC projects, venturing into new technologies such as Green Hydrogen, Green Ammonia etc.

जैव ईंधन पर बड़े गठबंधन का लक्ष्य

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 10 अगस्त

रूस, चीन व सऊदी अरब जैसे बड़े तेल उत्पादकों ने प्रस्तावित वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए) में शामिल होने को लेकर सहमति नहीं जताई है, ऐसे में भारत अब जी-20 समूह के बाहर के देशों को इसमें शामिल करने को लेकर सक्रियता से काम कर रहा है। इससे जुड़े कई अधिकारियों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि भारत का कूटनीतिक मिशन तमाम देशों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 और 10 सितंबर को होने वाले जी-20 के नेताओं के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और कवायद की जा रही है कि इसमें बड़ी संख्या में उपस्थिति रहे।

भारत ने जी-20 के ऊर्जा मंत्रियों की गोवा में हुई बैठक के दौरान इस मसले पर अलग से 22 जुलाई को वैश्विक सम्मेलन किया था। बातचीत के बाद घोषणा की गई थी कि 19 देशों ने इस गठजोड़ को पहल करने वाले सदस्य के रूप में शामिल होने में रुचि दिखाई है, जिनके नाम का खुलासा नहीं किया गया था।

बहरहाल सम्मेलन में जिन 7 देशों के ऊर्जा मंत्री शामिल हुए थे, उन्होंने एकमत होकर गठबंधन बनाने की समर्थन दिया था, जो जी-20 के सदस्य नहीं हैं।

इन देशों में बांग्लादेश, केन्या,



मॉरिशस, पराग्वे, सेशेल्स, यूएई और युगांडा शामिल हैं। एक अधिकारी ने कहा, 'जीबीए' में शामिल होने के लिए और देशों को आमंत्रित किया गया है। बड़ी संख्या में देशों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हमें अल्प विकसित देशों से भी प्रतिक्रिया मिली है। जब गठजोड़ बनेगा और नीतिगत लक्ष्य तय किए जाएंगे तो इन सभी विचारों को शामिल किया जाएगा।'

निकट पड़ोसी देशों के अलावा अफ्रीकी देशों की लंबी सूची है और लैटिन अमेरिकी देशों से भी समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिसमें अमेरिका का सहयोग भी अहम है, जिसने जीबीए को अपना समर्थन दिया है। शांघाई सहयोग समझौता समूह के मध्य एशियाई देशों से भी

भारत समर्थन की उम्मीद कर रहा है, जिन्होंने हाल ही में उभरती ईंधन तकनीक, ऊर्जा मॉडलिंग और परीक्षण लक्ष्यों में आपसी सहयोग का फैसला किया है।

लेकिन जी-20 समूह में रूस और सऊदी अरब अब तक गठजोड़ के पक्ष में पूरी तरह से नहीं आए हैं। उन्हें डर है कि यह गठजोड़ जीवाश्म ईंधन के खिलाफ माहौल पैदा करेगा, जो पहले से ही बन रहा है।

रूस और सऊदी अरब दोनों के बजट में कच्चे तेल की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है और वे परंपरागत हाइड्रोकार्बन में निवेश कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि चीन ने इस प्रस्ताव को लेकर थोड़ी सी रुचि दिखाई है।

इस गठजोड़ में चीन को शामिल होने के लिए मनाने में भारत कुछ ज्यादा कर पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच प्रमुख बहुपक्षीय पहलों को लेकर प्रतिस्पर्धा है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक चीन भी जैव ईंधन और कार्बन घटाने की नीति के साथ ईंधन पर्याप्तता योजना पर जोर दे रहा है, जैसे भारत एथनॉल पर जोर दे रहा है।

बहरहाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि रूस और सऊदी अरब जैसे साझेदारों की विश्वास में लिया जा रहा है और उनसे कहा गया है कि जीबीए मौजूदा क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम

जी-20 की तैयारी

■ वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के लिए सितंबर में होने वाले शिखर सम्मेलन के पहले भारत कर रहा है गैर जी-20 सदस्यों तक पहुंचने की कवायद

■ बहुपक्षीय पहल में अब तक रूस, सऊदी अरब और चीन ने शामिल होने को लेकर सहमति नहीं जताई, उन्हें जैव ईंधन के खिलाफ माहौल बनने का डर

■ वैश्विक एथनॉल उत्पादन में अमेरिका, ब्राजील और भारत की कुल हिस्सेदारी 85 प्रतिशत है, जो गठबंधन में शामिल होने को तैयार

हिस्सेदारी है। भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। इस तरह के गठजोड़ का वैश्विक असर यह है कि सभी प्रमुख हिस्सेदार पहले से तैयार हैं।' अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका ने आधिकारिक रूप से इसमें शामिल होने की तैयारी शुरू कर दी है।

एथनॉल पर नजर

गठबंधन का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रम के लिए तकनीकी सुविधा देने के लिए ठोस नीति विकसित करना, इसका बाजार मजबूत करना और वैश्विक जैव ईंधन व्यापार की सुविधा विकसित करना है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता है और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत के चीनी उद्योग को मांग आपूर्ति के अंतर चक्र्रीय मसले, कम राशि की पुनर्प्राप्ति और बर्बादी जैसे संकट से जूझना पड़ता है।

ऐसे में भारत में गन्ना किसानों की आजीविका हर चीनी विपणन सत्र में अधर में रहती है। सरकार इस संकट से निपटने के लिए गन्ने की आपूर्ति एथनॉल उत्पादन में बढ़ा रही है। भारत का जोर है कि परिवहन के काम आने वाले पेट्रोल में एथनॉल का हिस्सा बढ़ाया जाए।

नीति आयोग का मानना है कि वैश्विक गठबंधन बनने से वैश्विक सहयोग व्यवस्था बनेगी और इससे वैश्विक ईंधन बास्केट में जैव ईंधन की भूमिका बढ़ेगी।